डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की की नई ऊंचाई पर

राकेश शर्मा

मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की सरकार को सफल 2 वर्ष हो रहे हैं . विगत 2 वर्ष में मध्य प्रदेश ने तरक्की के नए सोपान प्राप्त किये हैं.कुशल नेतृत्व, दृढ़ इच्छा शक्ति और 24 घंटे मध्य प्रदेश वासियों की चिंता डॉक्टर मोहन यादव के व्यक्तित्व में समाहित है. मध्यप्रदेशवासी बड़े भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो 24 घंटे हर पल कैसे मध्य प्रदेशवासियों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके निरंतर उसके बारे में चिंतन करते हैं.आप किसी भी प्रदेश में चले जाएं वहां के निवासियों की पहली प्राथमिकता होती है कि वहां निरंतर विकास हो. मध्य प्रदेश तो विकास के नए आयाम गढ़ रहा है.

मध्य प्रदेश के युवा बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें डॉक्टर मोहन यादव जैसा मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ है, जिस दिन से डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उसी दिन से वह लगातार मध्य प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे प्राप्त हो उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं.देश में चाहे विदेश में सतत प्रवास कर उद्योगपतियों से वन टू वन मिलकर लगातार मध्य प्रदेश में नए उद्योग कैसे लगें और ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.मध्य प्रदेश में लगभग 32 लाख करोड़ के अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.प्रस्तावों को जल्दी-जल्दी धरातल पर उतारने के लिए वह लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि उद्योगपतियों से चर्चा कर उन्हें क्या-क्या सुविधाएं अपने उद्योग लगाने के लिए चाहिए, वह सब सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाएं.

मध्यप्रदेश सरकार ने उद्योगपतियों के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध कराई है साथ ही साथ ही उद्योगों के लिए जो चीज आवश्यक है वह सब सुविधा मध्य प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को उपलब्ध करा रही है. प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए इसके लिए बुनियादी सुविधाओं में लगातार काम हो रहा है. चाहे सड़कों का जाल हो या उद्योग के लिए बिजली पानी की व्यवस्था,मध्य प्रदेश में लगातार एयर कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है जहां-जहां बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं वहां पर सरकार एयरपोर्ट का निर्माण तेजी से कर रही है.भोपाल, इंदौर,ग्वालियर सहित कई एयरपोर्टों का उन्नयन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है.पूरे देश में उद्योग के लिए मध्य प्रदेश सरकार फ्रेंडली है यह आज उद्योगपति खुद कह रहे हैं और उद्योगपतियों में मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने की होड़ मची है. उद्योगों के साथ डॉ मोहन यादव किसानों की भी चिंता कर रहे हैं. किसानों के लिए बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है यह लगातार डॉ मोहन यादव विचार करते हैं और उसे अमली जामा पहनाया है.मध्य प्रदेश में भावांतर योजना हो या एमसपी बढ़ाने का काम हो,मध्य प्रदेश के किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद,बिजली, पानी प्राप्त हो रहा है लगातार सिंचाई का रखवा मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है जो किसानों के चेहरे पर एक नई खुशी लेकर आ रहा है. जो खेत पहले सिंचाई नहीं होने से बंजर हो रहे थे, वो अब लहलहा उठे हैं.

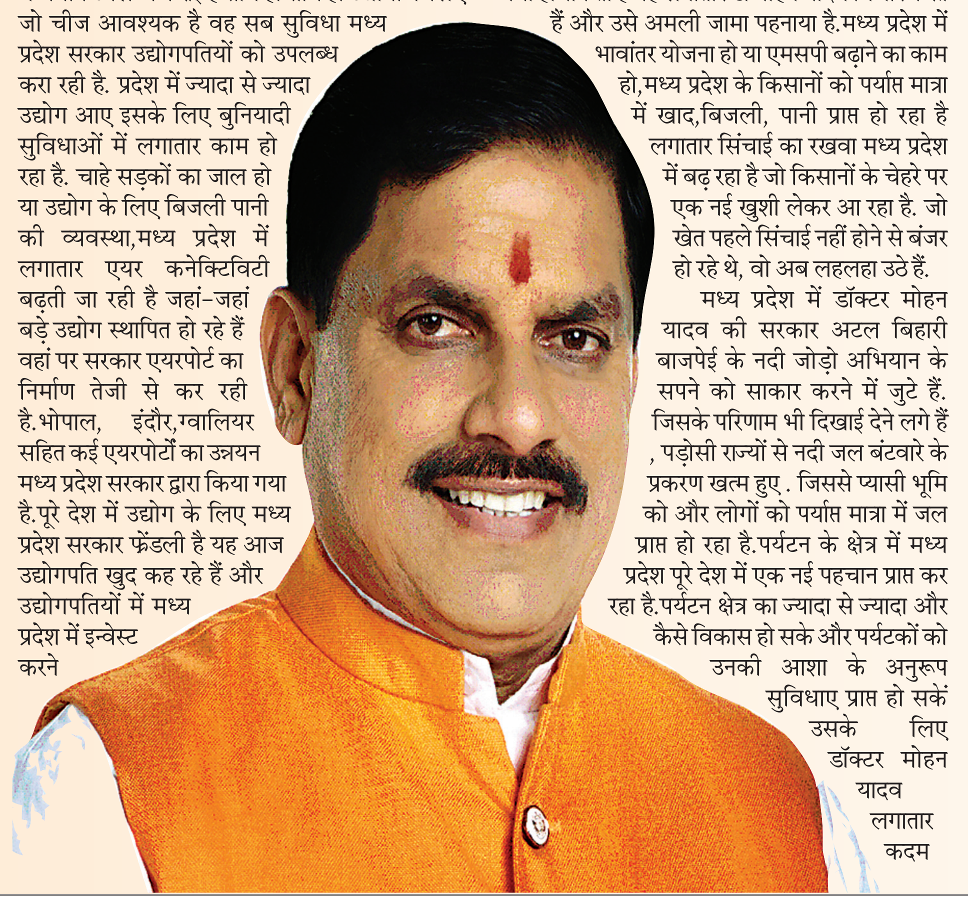

मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अटल बिहारी बाजपेई के नदी जोड़ो अभियान के सपने को साकार करने में जुटे हैं. जिसके परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं , पड़ोसी राज्यों से नदी जल बंटवारे के प्रकरण खत्म हुए . जिससे प्यासी भूमि को और लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो रहा है.पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश पूरे देश में एक नई पहचान प्राप्त कर रहा है.पर्यटन क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा और कैसे विकास हो सके और पर्यटकों को उनकी आशा के अनुरूप सुविधाए प्राप्त हो सकें उसके लिए डॉक्टर मोहन यादव लगातार कदम उठा रहे हैं. चीता प्रोजेक्ट और प्रदेश में बन रहे नए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका उदाहरण है . सामाजिक कार्यों में आज यह भी इतिहास में दर्ज हो गया कि डॉ.मोहन यादव सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया कि धार्मिक नगरी में पूर्णतः शराब बंदी होगी. इस कदम एवं ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत हर मध्यप्रदेशवासी ने किया. आज डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के प्रयासों से मध्य प्रदेश नक्सली मुक्त हो गया है.

देश में कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश का उच्च स्थान है.मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने अपने कपास उत्पादित करने वाले किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में धागा निर्माण के लिए नई फैक्ट्रियां लगाई जाएगी साथ ही कपड़ा उत्पादन यूनिट भी लगाई जाएगी, जिससे मध्य प्रदेश का अपना कपास,मध्य प्रदेश का अपना धागा,मध्य प्रदेश का अपना कपड़ा बने. बाहर से भी उद्योगपतियों को आमंत्रित कर कपड़े और धागे की फैक्ट्रियां अधिक से अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में लगे उसके लिए डॉक्टर मोहन यादव प्रयास कर रहे हैं और एक कहावत है प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती वह अगर आपको सच होती देखना है तो मध्य प्रदेश में यह सच हो रही है जिस तरह से नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है इससे जल्दी ही मध्य प्रदेश नशा मुक्ति प्रदेश होगा. नशे के सौदागरों को उनकी जगह जेल में पहुंचने का काम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है .मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव कदम उठा रहे हैं. सरकारी डॉक्टरों का वेतन बढ़ाने का काम हो या नहीं डॉक्टरों की भर्ती मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में भी निरंतर प्रयास कर रहा है . आज मध्य प्रदेश में नए चिकित्सा महाविद्यालय नए अस्पतालों का काम तेजी से हो रहा है पहले उंगलियों में गिन सकते थे अब नहीं मध्य प्रदेश में उज्जैन में सिहासत की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने जोरो से कर दी है.

> आज प्रदेश में हर व्यक्ति खुश है क्योंकि उसके लिए एवं उसके परिवार के लिए सतत मोहन यादव की सरकार काम कर रही है. बेहतर डेवलपमेंट स्वास्थ्य व्यवस्था पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में बिजली और सुरक्षा यह सब मध्य प्रदेश वासियों को डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उपलब्ध करा रही है. खुशहाल प्रदेश मध्य प्रदेश इस नारे को लेकर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार तेजी से कम कर रही है. आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है. स्वच्छता अभियान में लगातार इंदौर नंबर वन पर आ रहा है साथ ही मध्य प्रदेश के कई शहर स्वच्छता अभियान की सूची में शामिल है. दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश पूरे देश में ऊंचे स्थान पर कायम है. आज पूरे देश में मिलेट अनाज की बात होती है तो मध्य प्रदेश दूसरे पायदान पर आता है बाघ चिता प्रदेश मध्य प्रदेश है. यह हम मध्य प्रदेश वीसियो के लिए गर्व का विषय है. डॉ मोहन यादव की प्राथमिकता में निवेश ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में हो शामिल है. प्रदेश में नशे का सर्वनाश करने के लिए ठोस और आवश्यक कदम सरकार उठा रही है. यह मध्य प्रदेश के हित में है विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ चला है बढ़ चला है.

अतीत, वर्तमान और भविष्य को साथ लेकर चलने का संकल्प

मध्यप्रदेश में मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे

नरेंद्र शिवाजी पटेल
लेखक मध्यप्रदेश शासन के मंत्री हैं

मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार को दो वर्ष पूरे हो चुके हैं. इस अवधि में सरकार ने अतीत के सांस्कृतिक वैभव को पुनर्स्थापित करने, वर्तमान की प्रशासनिक चुनौतियों को साधने और भविष्य की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में कई पहलें की हैं. मुख्यमंत्री यादव ने अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर से ही प्रदेश की पहचान को सांस्कृतिक और विकासात्मक—दोनों स्तरों पर मजबूत करने की रणनीति अपनाई.

काल को तीन खंडों में विभाजित किया जाता रहा है, अतीत, वर्तमान और भविष्य. इन तीनों काल के लिए एक साथ कुछ करने की सामर्थ्य विरले ही व्यक्तित्वों में होती है. लेकिन तीनों कालों के लिए बहुत कुछ करने का चमत्कार बाबा महाकाल की नगरी के डॉ मोहन यादव ने दो साल की अवधि में कर दिखाया है. एक ओर जहां उन्होने मध्यप्रदेश के गौरवशाली अतीत को प्रभावी ढंग से संरक्षित और पुनर्स्थापित किया है, तो महाराज विक्रमादित्य के शासनकाल की झलक इन दो वर्षों के वर्तमान कार्यकाल में देखी जा सकती है. देश के इस हृदय प्रदेश को लेकर उनकी दूरगामी योजनाएं सुनहरे भविष्य के प्रति आश्वस्त करती हैं.

संतुलित नेतृत्व का संकेत

डॉ. मोहन यादव के दो वर्ष का कार्यकाल यह संकेत देता है कि सरकार अतीत के सांस्कृतिक गौरव, वर्तमान की प्रशासनिक प्राथमिकताओं और भविष्य की विकास योजनाओं—तीनों को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है. आने वाले समय में इन पहलों का वास्तविक असर प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में दिखाई देगा.

सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया. महाकाल कॉरिडोर के विस्तार कार्यों ने उज्जैन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है. राज्य के प्राचीन धरोहर स्थलों पर संरक्षण गतिविधियाँ तेज की गईं. ओंकारेश्वर क्षेत्र में अद्वैत दर्शन से जुड़े प्रकल्पों को गति दी जा रही है. भगवान श्रीकृष्ण के चरण मध्यप्रदेश की भूमि पर जिन स्थानों पर पड़े, उन्हे श्रीकृष्ण पाथेय में समाहित कर इनको तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है. इन पहलों का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है.

प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे पर फोकस

दो वर्षों में सरकार ने बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता दी है. प्रमुख सड़क मार्गों, औद्योगिक कॉरिडोरों और शहरी सुविधाओं को उन्नत करने के कार्य जारी हैं. ग्रामीण सड़कों का उन्नयन भी अभियान मोड में किया जा रहा है. शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी सुधार, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर काम किया गया है. कृषि क्षेत्र में उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं. महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाओं—जैसे लाड़ली बहना और स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम—के क्रियान्वयन पर भी जोर रहा.

निवेश, ऊर्जा और स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियाँ

राज्य सरकार ने आगामी दशक के विकास को लक्ष्य बनाते हुए कई योजनाएँ तैयार की हैं. नई औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय और बड़े निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिशें की जा रही हैं. पीथमपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं. सौर ऊर्जा उत्पादन, जल संरक्षण और इलेक्ट्रिक वाहन ढांचे को बढ़ावा देकर हरित ऊर्जा क्षेत्र में कदम तेज हुए हैं. स्वास्थ्य सुविधाओं को जिला एवं ग्रामीण स्तर तक मजबूत करने की दिशा में अस्पताल उन्नयन और टेली-मेडिसिन सेवाओं का विस्तार प्रस्तावित है.

चकाचौंध में 'तंत्र' कहां खो गया है?

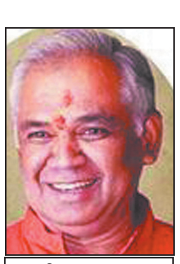

राजीव खण्डेलवाल
(लेखक कर सलाहकार एवं पूर्व बैतूल नगर सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

विगत दिवस देश के चकाचौंध से भरे दो ऐसे परिदृश्य सामने आए, जो तंत्र की वास्तविक स्थिति का आईना दिखाते ही नहीं बल्कि आगाह करते हैं कि देखिए सम्हल कर आईना, सामना आज है मुकाबिल का. ये दो उदाहरण बताने के लिए पर्याप्त हैं कि देश की चमक-दमक और जमीनी वास्तविकताओं के बीच खाई कितनी गहरी और चौड़ी है.

हवाई अड्डों का विस्तार एवं आधुनिकरण- नि:संदेह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में रिकॉर्ड विस्तार हुआ है. 2014 में देश में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, जो उसे देश का आम नागरिक (DAN) योजना के तहत बढ़कर आज 157 हो गए हैं. इसी अवधि में व्यावसायिक विमानों की संख्या 400 से बढ़कर 860 हो गई-लगभग 115त्न वृद्धि. फलस्वरूप आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है. प्रधानमंत्री का हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज मेंका वादा निश्चय ही इस विस्तार के पीछे प्रमुख आधार रहा है. एयरपोर्ट्स का आधुनिकरण इतना प्रभावी है कि भीतर प्रवेश करते ही विदेश होने की सुखद अनुभूति होती है.

एकाधिकार, डुओपॉली से मोनोपाली की ओर?- उक्त विकास ने एक नई गंभीर समस्या भी पैदा कर दी, जिसने वर्तमान संकट को गहराया है. विमानन बाजार पर आज इंडिगो (64 प्रतिशत) (2014 के 31.8प्रतिशत से बढ़कर) और एयर इंडिया (27.3 प्रतिशत) (8.4 प्रतिशत से बढ़कर) तथापि कुल 91.3प्रतिशत नियंत्रण का व एकाधिकार, पिछले चार-पांच दिन से हो रही हवाई यात्रियों की परेशानी का एक सबब है. देश का सबसे बड़ा (आठ) निजी एयरपोर्ट प्रबंधन अदानी समूह का दबदबा भी इसी दिशा की ओर संकेत करता है.

देश की सबसे बड़ी फ्लाइट ट्रेनिंग एवं सिमुलेशन संस्था के 72.8% शेयर्स अदानी समूह द्वारा अंतो नास्ति पिपासाया की युक्ति को चरितार्थ करते हुए उड़ाने रद्द होने के संकट पैदा होने के मात्र कुछ दिन पूर्व 27 नवम्बर को अधिग्रहित किए गए. यह भी एविएशन क्षेत्र में संभावित नई आशंका अति तृष्णा विनाशाय की ओर इंगित करता है. यह संयोग है अथवा प्रयोग? इसे इंडिगो के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में 15 सितंबर से नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत के जुड़ने के तथ्य के साथ देखिए?

घोर अव्यवस्था हजारों उड़ानें रद्द-लेकिन तंत्र मौन?- इसी बीच देश में 4 दिसंबर से 3000 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और हजारों उड़ानें देरी से चलीं. यात्री हवाई अड्डों पर मानो कसाई के खूंटे से बंधे असहाय यात्री बेहाल और घोर यातना मय स्थिति का सामना करते दिखे. हमेशा की तरह मेंनस्ट्रीम मीडिया प्राय: मौन रहा. यद्यपि देश की हवाई यात्राओं की दुर्दशा ने अर्नब (रिपब्लिक टीवी) की आत्मा को शायद कुछ समय के लिए जरूर जागृत कर दिया. उत्पन्न संकट की वास्तविक तस्वीर वस्तुत: सोशल मीडिया द्वारा ही सामने लाई गई. मूल समस्या पायलटों की भारी कमी थी. आवश्यक संख्या - 2422 उपलब्ध -1357 कम से कम 650-700 अतिरिक्त पायलट की जरूरत थी, जिसे कंपनी ने अनदेखा किया. इसके अतिरिक्त प्रतिदिन लगभग 2200 फ्लाइट चलने वाली इंडिगो ने 5 दिसंबर को पायलटों की कमी की तुलना में लगभग 1600 उड़ान रद्द की, यह भी एक जांच का विषय है. इंडिगो ने पायलट नहीं बढ़ाए, जबकि टाटा एयरलाइंस ने समय रहते 350 से अधिक पायलट नियुक्त किए, इसलिए उनका रद्दीकरण मात्र 1-2 प्रतिशत रहा. पायलट यूनियंस ने इंडिगो की लीन मैनपावर स्ट्रैटेजी (हायरिंग फ्रीज, पाय फ्रीज, नॉन-पोचिंग एग्रीमेंट्स) की कड़ी आलोचना की है, तथापि कोई आधिकारिक हड़ताल घोषित नहीं हुई. क्या इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि तंत्र के अपने हाथों से तराशी गई इंडिगो कंपनी ने FDTL नियम को लागू न करने के लिए ही से यह स्थिति निर्मित की? जिसमें वह सफल भी रही, क्योंकि डीजीसीए ने कंपनी को कोई सजा दिए बिना उक्त नियम लागू करने के लिए फरवरी 2026 तक का समय और देकर पायलट व यात्रियों की सुरक्षा को 'ताक' पर रख दिया.

डीजीसीए-अकर्मण्यता की पराकाष्ठा- हवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 22 माह पूर्व (जनवरी 2024) में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम जारी किए थे. इनका उद्देश्य था, पायलट की थकान (फटीग) कम करना. क्योंकि हवाई दुर्घटनाओं के पीछे 10-15 प्रतिशत कारण थकान ही पाया गया था. परंतु इंडिगो के समय बढ़ाने के बार-बार अनुरोध और दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से उक्त नियम चरणबद्ध तरीके से 1 जुलाई एवं 1 नवंबर 2025 से लागू किए गए. नियम लागू होने पर उसके परिपालन में कंपनी ने पर्याप्त संख्या में पायलट बढ़ाने की जगह उड़ानें ही रद्द कर दीं. सबसे चौंकाने वाली बात मनमानी के लिए कंपनी को दंडित करने के बजाय डीजीसीए ने सुरक्षा की दृष्टि से अपने बनाए नियम को ही फरवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दिए! यह तंत्र की शर्मनाक बेचारगी बेबसी नहीं तो क्या है? इससे भी बुरी हालत संकट प्रबंधन (क्राइसिस मैनेजमेंट) का भी बुरी तरह से विफल होना है. इस तरह की घटनाओं-आपदाओं से निपटने के लिए क्या पूर्व-निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है?

यही नहीं, मांग व पूर्ति के दबाव में अन्य हवाई कंपनियों के टिकट 6 गुना तक महंगे हो गए. रुपए गिरने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कथन रुपया अपने को खुद ही संभाल लेगा को डीजीसीए ने लपककर 'आत्मसात' कर लिया. जो अन्य विमानन कंपनियों के लाभ में सहायक सिद्ध हो रही है. संकट पैदा होने पर संकट पैदा करने वाली कंपनी और उस संकट का फायदा लेने वाली कंपनी दोनो को एक साथ फायदा फराहम करना, यही तो डीजीसीए का कमाल है. राजनीतिक नेतृत्व भी मुंगेरीलाल के हसीन सपनों की उड़ान में खोया हुआ है. डीजीसीए का अधिकतम 18,000 रु. किराया निर्धारित करने का आदेश भी हवा-हवाई हो गया. परंतु इस निर्देश का भी फायदा उठाकर कुछ टिकटें जो अभी सस्ती मिल रही थी, एविएशन कंपनियों ने उक्त सस्ती टिकटों को भी अधिकतम रेट तक ले गये. यानी भेड़ जब जहां जाएगी वहीं मुड़ेगी. एक उदाहरण-जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता के सी त्यागी, पूर्व सांसद को अपनी बेटी को मुंबई परीक्षा में भेजने के लिए रू. 9000 की इंडिगो की फ्लाइट निरस्त होने पर मजबूरी में एयर इंडिया की टिकट रू. 41,000 में लेनी पड़ी.

> स्वच्छ भारत अभियान में इस वित्तीय वर्ष में 12192 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है. बावजूद इसके मूलभूत रखरखाव भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है. इन दो उदाहरणों से स्पष्ट है कि इंफ्रास्ट्रर खड़ा करना ही पर्याप्त नहीं, उसे नियंत्रित व संचालित करने वाला 'तंत्र' भी उतना ही मजबूत होना चाहिए. विकास केवल इमारतें, रनवे, या चमकती स?कों से नहीं होता- बल्कि उनको संचालित नियंत्रण रखने वाली संस्थाओं की मजबूती से होता है. दुर्भाग्यवश पंखे से कोहरा छाटने की कोशिश में लगा यही तंत्र आज सबसे अधिक कमजोर, अकर्मण्य और असफल दिखाई देता है. इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह कि नियंत्रण रखने वाला तंत्र डीजीसीए दोषी कंपनी को सजा देने का न तो आशय रखता है और न ही सरकार अपने दायित्व को निभाने में असफल तंत्र डीजीसीए को सुधारने की दृढ़ इच्छा रखती है.
> शायद राम भरोसे इसी को कहते हैं.

व्यंग्य

सांसद का स्वान अनुराग.....

रवि उपाध्याय
(लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरु हो गया. बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बुलाया गए इस सत्र की भी उसी तरह हंगामेदार शुरुआत हुई जैसे पिछले ग्यारह सालों से संसद के हर सत्र की होती आ रही है. लगता है यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक विपक्ष सत्ता में नहीं आ जाता. इस सत्र की शुरुआत एक महिला सांसद, संसद में कुत्ते को लेकर आने से हुई. इस घटना से कुत्ते से ज्यादा चर्चा सांसद के कुत्ता प्रेम से हुई. बताया गया है कि वे जब संसद आ रहीं थीं तो उनकी नज़र सड़क पर से गुजर रहीं थीं तो उनका कुत्ते के प्रति एक मां की तरह वात्सल्य और ममता उमड़ने लगी और उन्होंने उसे अपनी लक्जरी कार में बैठा लिया.

यह घटना उनके कुत्तों के प्रति अनुराग और प्रेम को दर्शाती है. जब सांसद महोदया की गाड़ी ने संसद परिसर में प्रवेश करते हुए देखा तो उन्होंने ने अपने विशेषाधिकार की बात कही.प्रेस,मीडिया के लोग सांसद और कुत्ते को देख उधर ही दौड़ पड़े. कैमरे चमक उठे, वीडियो बनने लगे. न्यूज़ चैनलों पर महिला सांसद एवं उस भाग्यशाली कुत्ते की तस्वीरें नुमाया होने लगीं.

इस मौके पर रसखान कवि का वह दोहा या चौपाई, याद आ गया जिसमें कवि कोए के भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी . पूरा देश उस कुत्ते के भाग को सराह रहा है जिसे सांसद महोदया ने अपनी गोद में बैठाया. वरना सांसद किसी को भी मुंह लगाना तो दूर आम आदमी की तरफ़ तो देखतीं तक नहीं है. ये अब उस कुत्ते का भाग्य कहें या पिछले जन्म का संबंधों का पुण्य की सांसद ने उसे न केवल गोदी में बल्कि कार में भी लिफ्ट दी. अभी तक यह नहीं पता चला है कि कुत्ते का सेक्स क्या था ? वह मेल था या फीमेल.

इतना ही नहीं अपुन तो सांसद महोदया के कुकुर ज्ञान से भी चित हो गए. जिस तरह नेता दो प्रकार के होते हैं एक बड़े बड़े वायदे करने वाले दूसरे वायदों को पूरा करने वाले. उसी तरह सांसद ने ज्ञान दिया कि कुत्ते दो प्रकार के होते हैं. एक काटने वाले दूसरे चाटने वाले. सांसद जी ने बताया कि जिस कुत्ते को वे संसद दिखाने या घुमाने लाईं थीं वह काटने वाला कुत्ता नहीं था. जाहिर है कि फ़िर तो वो चाटने वाला रहा होगा. वैसे भी नेता अपने साथ चाटने वाले ही रखना ज्यादा प्रिफर्ड करते हैं. काटने वालों को तो नेता पहले ही नो - दो - ग्यारह कर देते हैं. काटने वाले तो उनके साथ वैसे भी नहीं होते हैं. हो सकता है कि उस भाग्यशाली पपी ने उसके प्रति ममता प्रदर्शित करने वाली सांसद महोदया को अपने उस गुण का कार में ही परिचय करा दिया हो. अब जो भी हो वैसे भी महिलाओं को इस प्राणी के प्रति अनुराग तो होता ही है. हमने कई मेम साहिबाओं को डॉग्स के साथ लक्जरी कारों में देखा है. कई मेमों को अंग्रेजी पप्पीज़ के साथ गोद में उठा चूमा चाटी करते हुए देखा है. हो सकता है कि सांसद मैडम को भी इस देशी पिल्ले पर प्यार उमड़ आया हो.

सांसद महोदया का देशी कुत्ते के साथ यह अनुराग अनूठा तो था ही साथ ही वह सियासी भी था. सियासी इस लिहाज़ से की उनके इस कदम से उन्हें वोटों का फायदा हो सकता है क्योंकि वोट देने का अधिकार तो केवल देशी लोगों को ही हासिल है. वैसे भी जो विदेशी घुसपैठिए हमारे देश में घुस आए हैं वे तो एस आई आर के चलते सिर पर पैर रख कर भाग ही रहें हैं. हो सकता है कि मोहतरमा के कुत्ता प्रेम से उनके वोट बैंक में और कुछ इज़ाफ़ा हो जाए. उन्होंने एक बात का खुलासा कर दिया कि जो वे अपने साथ कुत्ता लेकर आईं थी वह काटने वाला नहीं है.

उन्होंने ने बताया कि काटने वाले तो संसद में ही बैठे हैं. काटने और छांटने का काम तो सियासत में होता ही रहता है उनका इशारा किस तरफ था लेफ्ट साइड या राइट साइड . यह तो कोई नहीं बता सकता क्योंकि सदन में किसने किसको काटा है वही बता सकता है जिसे काटा गया हो या जिसने काटा हो. बाहरी लोग क्या बता सकते हैं कि सदन में कौन कटखना है और कौन चाट कर ही संतुष्ट हो जाता हैं.

हम तो इतना जानते हैं कि जिसे काटा जाता है वह पागल हो कर ऊटपटांग हरकतें करने लगता है. लेकिन यह पहली बार देखा गया कि कुत्ते को उठाने का असर इतनी तेजी से होता हो. कुत्ते को संसद परिसर में ले कर आने के दूसरे जब मीडिया ने उनसे उनके खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने पर उनकी टिप्पणी चाही तो वह भौं भौं कर कुत्ते की आवाज़ निकाल कर संसद के अंदर चलीं गईं. रही बात हमारी तो भैया हम तो नेताओं की अग़ाड़ी और पिछाड़ी दोनों से दूर रहते हैं कौन जाने कौन कब दुलत्ती मार दे और कौन कब हबक ले. चौदह इंजेक्शन कौन लगवाए.